Seventeenth Loksabha

p>

Title: Neeed to increase the Minimum Suppot Price of sugarcane growing farmers by the UP government.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय अध्यक्ष जी, देश को आज दो टुकड़ों में हम देख सकते हैं । 20 प्रतिशत शहरी और 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में किसान या किसान से जुड़ी हुई दूसरी जातियां रहती हैं । दुर्भाग्य की बात है कि कल किसानों पर 4-5 घंटे चर्चा हुई और कल एक विपक्षी पार्टी किसानों की बातें सुनने के बजाए अपने किसी एजीटेशन में लगी हुई थी । जहां तक सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी बीजेपी की सरकार है । श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं, वह कृपया इस तरफ ध्यान दें । इनके क्षेत्र में भी और दूसरी जगहों पर भी गन्ने की बहुत ज्यादा मात्रा में फसल होती है और जो प्रदूषण को भी कंट्रोल करने में मदद करती है । उसका बड़ा पेड़ होता है । 3 साल से उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई है । किसानों के हजारों करोड़ रुपये बकाया हैं । उनकी रोजी-रोटी नहीं चल रही है । ऐसी स्थिति में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में एक बार 8 प्रतिशत महंगाई बढ़ी । एक बार 7 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के करीब महंगाई बढ़ी । महंगाई बढ़ी है तो कम से कम रेट को बराबर करने के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ने का रेट है, उसको बराबर करने के लिए 100 रुपये के आसपास बढ़ाया जाए । सरकार की जो नीति है कि किसान की डबल आय करेंगे । उस हिसाब से 400 का 800 बैठता है । इस हिसाब से प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि कम से कम 500 रुपये जरूर कर दिये जाएं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरीश चन्द्र को श्री मलूक नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।